**Passenger traffic Service in Sealdah, Division of Eastern Railway**

3390. SHRI TRIDIB CHAUDHURI:
SHRI PIUS TIRKEY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the complaint of travelling public about the steady deterioration of passenger Traffic Service in the Sealdha Division of Eastern Railway and the late running of local trains for commuters to and from Calcutta-Sealdah; and

(b) any steps taken to redress the complaints and improve the service?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). The Railways are fully seized of the problems of commuters traffic in the Sealdah Division of Eastern Railway. The running of suburban train service on Sealdah Division has been affected mainly due to miscreant activities, thefts, and limited availability of spares. Within the prevailing constraints Railways are making all efforts for remedial measures to overcome the irregularities related to suburban trains. Many of the 8 coach EMU rakes on Sealdah Division have already been replaced by 9 coach rakes. As and when additional EMU coaches become available, further relief would be provided by converting the existing 8 coach rakes into 9 coach rakes. Close liaison is also being maintained with the West Bengal State Government to check the incidence of miscreant activities.

**राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक**

3391. श्री कृष्णदत्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के परिवहन मंत्रियों की पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन बैठकों में लिए गए निर्णयों की एक प्रति को सभा पटल पर रखने का है ; और

(ग) उनमें हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री ने क्या सुझाव दिए हैं और सरकार का उन सुझावों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है, तथा उनका ब्यौरा क्या है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). पिछले एक साल में राज्यों के परिवहन मंत्री सिर्फ अगस्त, 1980 में हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में एक बार आपस में मिले । परिषद् की सिफारिशों में अलग-अलग विषय पर सलाह दी जाती है और हम उन सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं । परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां संसद् के सभा पटल पर रखने की न तो परिपाटी रही है और न ही ऐसा जरुरी समझा गया है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने परिवहन विकास परिषद् की बैठक में विचार विमर्श के दौरान ये ये बात रखीं:—

(i) चैसिस सप्लाई करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य को वरीयता दी जाए,

(i) हिमाचल प्रदेश का नाम ईस्ट जोन परमिट स्कीम में एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए ;

(iii) इस्पात और सीमेंट जैसी जरूरी चीजों के अभाव के कारण सड़कों के निर्माण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए राज्य सरकार को अधिक इस्पात और इस्पात की छड़े आबंटित की जाएं ।

(iv) पर्यटकों के बढ़ते हुए यातायात को नियंत्रित करने के लिए टूरिस्ट टैक्सियों के परमिट भी बढ़ाए जाएं ।

यह फैसला किया गया था कि चैसिस की सप्लाई के बारे में चैसिस निर्माताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उसमें विचार विमर्श किया जाए । तदनुसार, क्षेत्रीय बैठक बुलाने की योजना बनाई गयी है । 31-10-1980 को एक बैठक बुलाई गयी जिसमें उत्तरी राज्यों के राज्य सड़क परिवहन निगमों की चैसिस संबंधी आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया । लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं आए । जहां तक हिमाचल प्रदेश का नाम ईस्ट जोन की जोनल परमिट स्कीम में शामिल करने का सवाल है सितम्बर, 1980 में अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग द्वारा बुलाई गयी बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया गया था कि एक ऐसे राज्य को जो पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ नहीं लगता, पूर्वी क्षेत्र स्कीम में शामिल करना संभव नहीं है । पूर्वी क्षेत्र में 10 राज्य आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं :- बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आसाम । टूरिस्ट टैक्सियों के परमिटों की संख्या में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन है ।

**Scheduled Tribes Candidates**

3392. SHRI BHEEKHABHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether it s a fact that in the matters of recuitment of Scheduled Tribes candidates, there have been shortfalls in almost all the railway zones?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Yes.

**Co-operative Agreement with Mozambique**

3393. SHRI KESHAORAO PARDHI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to provide vital co-operation to Mozambique in the fields of agriculture, small scale industries improvement and expansion of railways rubber and tea industries;

(b) whether any agreement has been reached in this regard; and

(c) if so, the detailed outlines of this agreement?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) to (c). No formal agreement has been concluded on the subject. However, details of co-operation in these fields were included in the agreed minutes signed at the end of the visit of the Mozambican Minister of Ports and Surface Transport on 29-10-1980. Co-operation in the field of agriculture would cover crops, agro-based industries and research. A team of four experts would be deputed to Mozambique for a study on rubber plantation followed by a feasibility study for setting up such plantations there. India and Mozambique would cooperate in tea processing and in establishing tea proce-